दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

गडकरी होने का अर्थ

नितिन गडकरी एक अलग किस्म के राजनेता हैं। खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वे खाने के शौकीन हैं। सज-धज में रहते हैं और लगता है कि जीवन का आनंद ले रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित करने में मजा आता है और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में किसी चीज की फिक्र नहीं है उन्हें।

इसके साथ ही वे एक स्वयंसेवक भी हैं। माना जाता है कि वे आरएसएस के प्रिय हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र, नागपुर (महाराष्ट्र) का पूरा खयाल रखते हैं और आरएसएस, अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी खुश रखते हैं।

गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही नागपुर के हैं और उनके समर्थक उसी क्षेत्र, उसी राजनीतिक आधार, नेताओं और कार्यकर्ताओं से आते हैं। महाराष्ट्र में चर्चा है कि गडकरी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके मंसूबों को विफल कर दिया। मोदी ने अपने निष्ठावान देवेंद्र फडणवीस को चुना। समझा गया कि गडकरी की महत्त्वाकांक्षाओं, अगर कोई हो तो, को काबू में रखने के लिए यह एक चतुराई भरा कदम था। लेकिन किसी के काबू न आने वाले गडकरी ने फिर भी तरीके खोज लिए और अपने लिए रास्ता बना लिया।

गडकरी उवाच

गडकरी को अपने मंत्रालयों- राजमार्ग और सड़क परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा शुद्धिकरण- पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखने वाला माना जाता है। मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन का रिकार्ड मिला-जुला रहा है। राजमार्गों के निर्माण में बढ़िया, गंगा शुद्धिकरण के नाम पर प्रचार, जल संसाधन विकास में आशा से कम, और सिंचाई परियोजनाओं में खेदजनक रूप से पीछे।

अपने दफ्तर के बाहर, बोल-चाल में वे एकदम बेबाक और स्पष्टवादी हैं। मार्च, 2018 में, मीडिया की ओर से आयोजित एक कॉनक्लेव में उन्होंने कहा, 'अतीत में कई बार अच्छे दिन को लेकर मीडिया हमें सवालों के जाल में फंसा चुका है। मैंने क्या कहा, कृपया उसकी गलत व्याख्या न करें। यहां अच्छे दिन जैसी कोई बात नहीं है... अच्छे दिन एक विश्वास है, अगर आपको भरोसा है तो यह है।' फिर अगस्त 2018 में जब आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन सिर उठा रहा था, उन्होंने कहा, 'आरक्षण दे भी दें, लेकिन नौकरियां तो हैं नहीं। तकनीक के कारण बैंकों में नौकरियों के अवसर घट गए हैं, सरकारी भर्तियां ठंडे बस्ते में हैं।' बहुत से लोगों को शुबहा हुआ कि गडकरी के निशाने पर आंदोलनकारी (आरक्षण की मांग करने वाले) नहीं, बल्कि रोजगार सृजन में विफल मोदी सरकार थी।

हाल में अपने चतुराई से दिए गए बयानों से वे छोटे-मोटे बवंडर खड़े करते रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव नतीजों ने उन्हें एक सुनहरा मौका उपलब्ध कराया। उन्होंने अपनी बात रखने में कोताही नहीं की। उन्होंने कहा, 'सफलता के बहुत से बाप हैं, लेकिन विफलता हमेशा लावारिस होती है, और जब सफलता थी तो इसका श्रेय लेने की होड़ थी, लेकिन विफलता की स्थिति में लोग एक-दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। नेतृत्व को अपनी हार और विफलता स्वीकार करना भी आना चाहिए। संगठन के प्रति नेतृत्व की निष्ठा तब तक साबित नहीं होगी जब तक कि वह हार के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता।'

गणतंत्र दिवस, 2019 को वे और भी मुखर थे : 'जनता उन राजनीतिक नेताओं को पसंद करती है, जो उन्हें सपने दिखाते हैं। लेकिन अगर ये सपने पूरे नहीं हुए तो जनता इन नेताओं की पिटाई भी करेगी।'

चुनौती की तैयारी

किसी के भी दिमाग में इस बात को लेकर संशय नहीं था कि निशाने पर मोदी थे। अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या सरकार बनाने में खुद को अक्षम पाती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस स्थिति में गडकरी पार्टी में नेतृत्व के लिए मोदी को चुनौती देंगे।

इससे पहले गडकरी इशारों में ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी लपेट चुके हैं। चौबीस दिसंबर, 2018 को आइबी इंडोमेंट लेक्चर में गडकरी ने कहा, अगर मैं पार्टी अध्यक्ष हूं और मेरे सांसदों, विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? मैं हूं।' उसी कार्यक्रम में उन्होंने एक गुगली प्रधानमंत्री की ओर भी फेंकी : सहिष्णुता भारतीय व्यवस्था की सबसे बड़ी संपदा है। सिर्फ अच्छा भाषण देने से आप चुनाव नहीं जीत सकते... आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन लोग आपको वोट नहीं देंगे। जो यह समझता है कि वह सर्वज्ञ है, गलती कर रहा है- लोगों को कृत्रिम मार्केटिंग से परहेज करना चाहिए।

गडकरी वे सारी बातें कह चुके हैं, जो भाजपा का एक असंतुष्ट कह सकता है और जिसे सारे विपक्षी नेता कहेंगे। वे परोक्ष रूप से लगभग प्रधानमंत्री को सपनों का नाकाम सौदागर करार दे चुके हैं और हार की जिम्मेदारी लेने की उनकी अनिच्छा के लिए झिड़की भी दे चुके हैं; वे प्रधानमंत्री पर असहिष्णुता और कृत्रिम मार्केटिंग में लिप्त होने का आरोप भी लगा चुके हैं। निस्संदेह, एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी की ओर से ये काफी सख्त अल्फाज हैं।

भौंचक्का नेतृत्व

इन तमाम बयानों के बावजूद भाजपा नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से एक शब्द भी नहीं कहा है। आरएसएस ने भी गडकरी को फटकार नहीं लगाई है। संभवतः वे चकराए हुए हैं और उन्हें सूझ नहीं रहा कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। मुझे शक है कि किसी कार्रवाई को लेकर उनकी झिझक इसलिए भी है कि पार्टी नेतृत्व जानता है कि गडकरी जैसे और भी नेता हैं- खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सांसद- जो लोकसभा चुनावों के नतीजों और अपने राजनीतिक भविष्य के प्रति आशंकित हैं। 2014 में भाजपा और उत्तर प्रदेश में इसके सहयोगी (अपना दल) ने इन चार राज्यों में दांव पर लगी 145 में से 135 सीटें जीती थी। किसी भी गुणा-भाग के हिसाब से इस बार भाजपा इन 135 से 80 सीटें गंवाने के कगार पर है। गडकरी और उनके समर्थकों को शिद्दत से बस इसी नतीजे का इंतजार है। इसकी चर्चाएं रोजाना तीव्रतर हो रही हैं और गडकरी एवं उनके उत्साही समर्थकों के कानों में मिसरी घोल रही हैं!

और भी ऐसी आवाजें उठने लगी हैं (नवीनतम रामविलास पासवान) जो भविष्यवाणी कर रही हैं कि चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या 282 से नीचे आने वाली हैं। अब जब, यह फिसलन जारी है, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि इसी के साथ गडकरी के श्रीमुख से निकले बयानों की पुनरावृत्ति भी बढ़ेगी!

विषमता की जड़ें

नरपत दान चारण

भारत के संदर्भ में ऑक्सफेम की ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 में देश के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में उनतालीस फीसद का इजाफा हुआ है, वहीं पचास फीसद गरीब आबादी की संपत्ति में महज तीन फीसद की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल भारतीय अरबपतियों की संपत्ति प्रति दिन 2200 करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं देश की 77.4 फीसद संपत्ति पर दस फीसद अमीर लोग काबिज हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग 2004 से कर्जदार बने हुए हैं। गौरतलब तथ्य यह भी सामने आया है कि 2018 में अठारह नए अरबपति बने, इस तरह अब देश में कुल अरबपतियों की संख्या एक सौ उन्नीस हो गई है, जिनकी संपत्ति पहली बार बढ़ कर चार सौ अरब डॉलर के स्तर को पार कर गई है। ऑक्सफेम ने अनुमान लगाया है कि 2018 से 2022 के बीच भारत में रोजाना सत्तर नए करोड़पति बनेंगे। इस सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि सरकारों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं का कम वित्तपोषण करके, अमीरों पर कम कर लगा कर तथा कर चोरी रोकने के पुख्ता इंतजाम न कर पाने से असमानता बढ़ रही है।

इस रिपोर्ट में खास और चिंताजनक बात यह बताई गई है कि इस आर्थिक असमानता में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता लगातार कायम है। गौरतलब है कि विकास की मौजूदा प्रक्रिया के कारण एक तबके के पास हर तरह की विलासिता के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है और दूसरी तरफ गरीब लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। गरीबी उन्मूलन के प्रयास तो हो रहे हैं, मगर वह नाकाफी है। तभी तो एक वर्ष में गरीबों की आय में महज तीन फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। यह चिंताजनक है।

मुद्दा

> देश की गरीब आबादी को आय के सम्मानजनक स्तर तक लाना ही होगा। गरीबी उन्मूलन के लिए खाका बना कर नई कार्ययोजना को त्वरित रूप से क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है, ताकि फासले को पाटा जा सके।

देखने में आ रहा है कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के जिस उदारीकरण और निजीकरण के समर्थक मॉडल को अपनाया गया है वह अमीर और गरीब की खाई को पाटने के बजाय और अधिक चौड़ा कर रहा है। पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखने पर नजर आता है कि देश में दस फीसद पूंजीपति लोगों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी ओर दस फीसद आम लोगों की आय में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। घरेलू उत्पाद में खरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं कृषि में जीडीपी का स्तर घट रहा है। एक तरह से विकास दर से संबंध उद्योगपतियों और कारोबारियों तक ही सीमित हो रहा है। आवश्यकता समावेशी विकास की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करने की है, मगर धरातल पर असमानता है।

विकास का पैमाना आर्थिक और सामाजिक समानता कायम करने वाला और गरीबों के जीवन स्तर को तीव्र गति से ऊंचा उठाने वाला होना चाहिए। बड़ी आबादी के पास आय के साधन नहीं हैं, अर्थतंत्र में यह बदलाव देश की गरीब आबादी के लिए नकारात्मक पहलू है। अब सवाल है कि क्या विकास का यह पैमाना उचित है, जो देश को अमीर-गरीब के साथ ही कृषि-उद्योग और गांव-शहर के बीच बांट कर विषमता को बढ़ाने का काम कर रहा है। आर्थिक विकास की वर्तमान प्रक्रिया क्या इस दशा में परिवर्तन लाने में सहायक हो पाएगी। हमारी वर्तमान विकास नीति का लक्ष्य और दर्शन क्या है? यह भी स्पष्ट होना चाहिए। जो सारे आर्थिक विशेषाधिकार मेट्रो सिटी के एक खास पूंजीपति तबके के पास ही कायम है, वह गैरकानूनी आय और कालेधन की समांतर अर्थव्यवस्था की भी उपज है। गरीबी बढ़ने का यह भी एक प्रमुख कारण है।

आर्थिक असमानता की वजह से आम लोगों के जीवन स्तर में कमी के साथ ही कई और समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर कुंठा को जन्म देती है। समाज के आर्थिक रूप से निचले स्तर पर आजीविका के लिए संघर्षरत किसी व्यक्ति के लिए नैतिकता और ईमानदारी अपना मूल्य खो देती है। यानी इससे सामाजिक असमानता भी जन्म लेती है, जो टकराव का कारण बनती है। ध्यान देना होगा कि चंद हाथों में सिमटी समृद्धि की वजह से देश का एक बड़ा वंचित तबका अमानवीयता से शून्य अपसंस्कृति का शिकार हो रहा है। एक राष्ट्र में उच्च और निम्न स्तर के लोगों के दो भाग एक तरह से राष्ट्र का आंतरिक आर्थिक विभाजन है। देश का एक बड़ा तबका जो अकुशल है, जिसे शिक्षा और तकनीक का ज्ञान नहीं है, वही गरीब है। अगर इनके हाथों में गृह उद्योग और लघु ग्रामीण उद्योग दिए जाएं तभी ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों का जाल छोटे-छोटे कस्बों तक फैला रखा है, जो गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है, क्योंकि इससे कुटीर और लघु उद्योग की वस्तुओं की बिक्री नहीं हो पाती।

गरीबों को हुनर और काम देने के साथ ही उनके समग्र जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास होना चाहिए। कर्ज माफी और मुफ्त सुविधाएं देना गरीबी को चिरस्थायी बना कर उनका राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति मात्र है। बढ़ते पूंजीवाद के कारण नव-उदारवादी नीतियों तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियां गरीबों के लिए अहितकारी साबित हुई हैं। गरीबों की कीमत पर बढ़ती अमीरी गरीबी निवारण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन गई है। आधुनिक आर्थिक अवधारणा विषमता को बढ़ने से रोकने में सफल नहीं हो पाई है। गरीबी नियंत्रण के लिए सरकार को कुछ त्वरित कदम उठाने की जरूरत है, जैसे ग्रामीण अर्थव्यस्था की मजबूती के लिए, पशुपालन और कृषि में तकनीकी सुधार के साथ सुविधाएं और प्रोत्साहन देना होगा। स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। गांवों को स्वरोजगार केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जानी चाहिए। साधनों के निजी स्वामित्व, आय और साधनों के असमान वितरण और प्रयोग पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। अमीरों की पूंजीवादी नीतियों में बदलाव करके उसे वंचित लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। भारत में कंपनियों के शीर्ष एक्जीक्यूटिव का वेतन करोड़ों में है, वहीं ग्रामीण गरीबों के पास श्रम और आय की दिनों दिन कमी होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण भारत के विकास को मुख्यधारा से जोड़े जाने की जरूरत है।

अब कई अर्थशास्त्री यह मानने लगे हैं कि गांधीजी द्वारा बताए गए मार्ग को छोड़ कर देश ने बड़ी गलती की है, जिसका खमियाजा गरीबी के साथ आज हम भुगत रहे हैं। गांधीजी का मानना था कि कृषि विकास हमारी योजनाओं का मुख्य आधार होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर गृह उद्योग तथा ग्रामोद्योग की रूपरेखा गांवों के विकास के लिए बनानी चाहिए। आज कृषि और गृह उद्योग दोनों हाशिए पर हैं। अमीरों को भी गांधी दर्शन सादगी और भौतिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण का मार्ग दिखाता है, जो गरीबों के कल्याण के लिए भी उपयोगी है। लोकतंत्र विभिन्न वर्गों के लोगों के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संसाधनों को सार्वजनिक हित में लगाने की कला है। अब देश की गरीब आबादी को आय के सम्मानजनक स्तर तक लाना ही होगा। गरीबी उन्मूलन के लिए खाका बना कर नई कार्ययोजना को त्वरित रूप से क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है, ताकि फासले को पाटा जा सके।

गरीबी बांटने की परंपरा

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

कभी वे दिन थे, जब कांग्रेस अध्यक्ष इतनी अजीब, इतनी रहस्यमयी बातें किया करते थे कि हम राजनीतिक पंडित विश्लेषण कर ही नहीं पाते थे। याद है, जब उन्होंने दलितों को नसीहत दी थी कि उनको आगे अगर बढ़ना है, तो उनको वृहस्पति ग्रह की रफ्तार से चलना होगा! याद है, जब उन्होंने कहा था कि भारत देश नहीं है, मधुमक्खियों का छत्ता है! इस बात को हम तो समझ नहीं पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी समझ गए कि यह ऐसा पत्ता फेंका है राहुल गांधी ने, जो 2014 के आम चुनावों में बहुत काम आएगा। सो, 'शहजादे' का मजाक जब उड़ाया करते थे चुनाव अभियान में तो हमेशा याद दिलाते थे कि 'जिस भारत को हम माता समझ कर पूजते हैं, उसको शहजादे मधुमक्खियों का छत्ता समझते हैं।' फिर जब राहुलजी ने कहा कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है, तो इसको मोदी ने तुरुप का पत्ता बनाया 2014 में। राजनीतिक पंडितों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का यह वक्तव्य इतना रहसमय था कि इसका विश्लेषण करने की तकलीफ ही नहीं किसी ने उठाई।

> अच्छा हुआ कि आने वाले आम चुनावों से पहले ही हम जान गए हैं कि राहुल गांधी के राजनीतिक और आर्थिक विचार क्या हैं। अच्छा हुआ कि हम समझ गए हैं कि वे अपने परिवार की गरीबी बांटने वाली परंपरा को कायम रखेंगे।

हाल में राहुलजी में परिवर्तन दिखने लगा है। अपने राजनीतिक और आर्थिक विचारों को अब स्पष्ट तरीके से बयान करने लगे हैं अपने भाषणों में। सो, राजनीतिक तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी दृष्टि में भारत के दो हिस्से हैं- एक है अमीरों, धनवानों का भारत, जो नरेंद्र मोदी का भारत है और दूसरा है गरीबों, किसानों, मजदूरों का भारत, जिसकी सेवा उनकी कांग्रेस पार्टी करती आई है और भविष्य में करना चाहती है। इस दूसरे भारत को ध्यान में रख कर उन्होंने पिछले हफ्ते रायपुर की एक आमसभा में ऐलान किया नाटकीय अंदाज में कि उनकी सरकार जब बनेगी तो हर गरीब भारतीय को न्यूनतम आमदनी की गारंटी दी जाएगी, ताकि 'न कोई भूखा रहेगा हिंदुस्तान में और न कोई गरीब।'

नेक दिल हैं कांग्रेस अध्यक्ष और गरीबों के लिए दर्द भी है उनके दिल में, लेकिन उनके आर्थिक विचार इतने पुराने हैं कि उनका यह भाषण सुन कर मुझे उनकी दादी का दौर याद आया। याद आया वह 1971 वाला आम चुनाव, जिसमें उन्होंने पहली बार 'गरीबी हटाओ' का नारा बुलंद किया था। इतना लोकप्रिय हुआ यह नारा कि इंदिराजी के नाम से जुड़ गया। इसके बाद हर चुनाव में इंदिराजी याद दिलाना नहीं भूलती थीं कि 'वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ।'

गरीबी हटाने पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए इंदिरा गांधी के दौर में, लेकिन गरीबी नहीं हटी। उनके बाद जब उनके बेटे राजीव प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी गरीबी हटाने का खूब प्रयास किया, लेकिन पाया उन्होंने कि गरीबों तक हर सरकारी रुपए के सिर्फ पंद्रह पैसे पहुंचते थे। यानी गरीबी हटाने के लिए जिन समाजवादी आर्थिक नीतियों को उन्होंने अपनाया था, वे तकरीबन पूरी तरह नाकाम रहीं। गरीबी तभी कम होने लगी भारत देश में, जब सोनिया गांधी ने नरसिंह राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त करके निजी निवेशकों को आमंत्रित किया अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए। इसके बाद ही देखने को मिले हैं भारत में संपन्नता और समृद्धि के थोड़े-बहुत आसार। गरीबी हटी तो नहीं है, लेकिन इस हद तक कम हुई कि भारत अति-गरीब श्रेणी से निकल कर आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने देखने लगा है।

नरसिंह राव की आर्थिक दिशा लेकिन सोनिया गांधी को पसंद नहीं थी, सो जब उनकी बारी आई, उन्होंने वापस वही आर्थिक रास्ता चुना, जो इंदिरा गांधी ने चुना था गरीबी हटाने का वादा करके। इस रास्ते पर चलने वाले राजनेता लेकिन गरीबी हटाने के नाम पर अक्सर सिर्फ गरीबी बांटने का काम करते हैं, क्योंकि स्पष्ट करते हैं कि धन पैदा करने वाले लोग उनकी नजरों में खलनायक हैं, जो धन पैदा करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जनता की भलाई के लिए नहीं। सो, धन पैदा करने का काम सरकार को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। यही है समाजवादी विचारधारा का बुनियादी सिद्धांत।

समस्या यह है इस सोच में कि सरकारें ज्यादातर पैसा खर्चना जानती हैं, पैसा बनाना नहीं। सो, गरीबी हटाने की जिन विशाल योजनाओं को तैयार करती हैं, उनके लिए पैसा हमेशा कम पड़ जाता है। जो मिलता है उसका भी काफी हिस्सा गरीबों को न जाकर सीधा जाता है भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं की जेबों में। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक सोच स्पष्ट करने की शुरुआत की है, साफ दिखने लगा है कि वे गरीबी बांटने का काम करेंगे, उसे हटाने का नहीं। हटा कैसे सकेंगे जब उनकी नजरों में धन पैदा करने वाले जो मुट्ठी भर लोग हैं भारत में, वे सब चोर हैं जो इस देश के उस भाग में रहते हैं, जहां रहते हैं नरेंद्र मोदी के 'सूट-बूट' वाले दोस्त।

यही सूट-बूट वाले हैं राहुलजी, जिनके पैसों से आपकी न्यूनतम आमदनी वाली योजना के लिए पैसे आ सकते हैं, लेकिन इनको ही आप दुश्मन बना बैठेंगे तो आपको क्यों देंगे आपकी इस महान गरीबी हटाने वाली योजना के लिए पैसा? शायद उनके किसी करीबी दोस्त या सलाहकार ने कुछ इस तरह की बातें कही होंगी उनके भाषण के बाद, क्योंकि अगले दिन ही राहुल गांधी की तरफ से एक दूसरा वक्तव्य आया, जिसमें उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनको हर अमीर हिंदुस्तानी से नफरत है, नफरत उनको सिर्फ नीरव मोदी जैसे लोगों से है।

जो हो, अच्छा हुआ कि आने वाले आम चुनावों से पहले ही हम जान गए हैं कि राहुल गांधी के राजनीतिक और आर्थिक विचार क्या हैं। अच्छा हुआ कि हम समझ गए हैं कि वे अपने परिवार की गरीबी बांटने वाली परंपरा को कायम रखेंगे।

खेल पलटने का खेल

पहला 'गेम चेंजर' : प्रियंका कुलवक्ती राजनीति में आईं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनीं।

हर चैनल पर प्रियंका के पुराने फुटेज तैरने लगे। दिलजले जलने लगे।

एक एंकर : इसका मतलब राहुल फेल! जी नहीं राहुल पास!

हाय हाय 'गांधी डाइनेस्टी'! वंशवाद वंशवाद! बहन और भाई एक साथ!

चैनल बोले : प्रियंका गेम चेंजर! प्रियंका गेम चेंजर!

पहले ही क्या चमत्कार किया था, जो अब उत्तर प्रदेश में करेंगी?

कांग्रेसी प्रवक्ता : प्रियंका पूरे देश की हैं, उनमें करिश्मा है।

न्यूज अठारह : उनका चेहरा इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। एक ओर इंदिरा का चेहरा लगा रहा, दूसरी ओर प्रियंका का चेहरा लगा रहा।

हर एंकर के लिए : प्रियंका गेम चेंजर! हाय! उत्तर प्रदेश का गणित बिगड़ा।

हर चैनल पर एक ही सवाल रहा : किसका गणित बिगाड़ेंगी प्रियंका?

एक एंकर : सपा-बसपा का गणित बिगाड़ेंगी प्रियंका!

दूसरा : भाजपा का गणित भी बिगाड़ेंगी प्रियंका!

इंडिया टुडे ने लाइन लगाई : क्या प्रियंका यंग इंडिया को साथ ला सकती हैं।

इसके बाद एक भाजपा नेता का सौंदर्यबोध आहत हुआ। वे कह उठे 'चाकलेटी चेहरा!'

एक एंकर नाराज होकर बोलीं : ये कैसा 'सेक्सिस्ट कमेंट' है। ये 'मिसोजिनस्टिक मांइडसेट' है।

इस बीच एक अंग्रेजी चैनल हिंदी में आने की कहने लगा। अंग्रेजी एंकर ठीकठाक-सी हिंदी बोलने लगा। चलो अंग्रेजी को भी हिंदी में आना पड़ा!

बलिहारी ब्रेकिंग न्यूज की कि ज्यों ही चंदा कोचर आदि पर एफआइआर की खबर आई, त्यों ही एक बड़े मंत्री द्वारा सीबीआइ को चेताने की खबर ब्रेक हुई कि सीबीआइ अधिक दुस्साहस न दिखाए और हे प्रभु, एक बंदे का तुरंत तबादला हो गया!

इसे कहते हैं : 'जाको राखे साइयां मार सके न कोय!'

इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने ऐलान कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, तो हम चौबीस घंटे में मंदिर बना सकते हैं!

इसके बरक्स सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ऐलान किया कि मंदिर का मुद्दा दस सेकंड में निपट सकता है!

इतनी सुंदर जुगलबंदी के दिनों में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी पता नहीं क्यों अक्सर कुछ विषम स्वर लगा दिया करते हैं कि सबका जी खट्टा हो जाता है। इस बार भी लगा दिए कि नेता जब सपने दिखाते हैं, तो अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते तो जनता पिटाई भी करती है।...

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित स्थल को छोड़ बाकी सड़सठ एकड़ अविवादित जमीन को अधिग्रहीत करने की अनुमति दी जाए, ताकि उसे रामजन्म भूमि न्यास को दिया जा सके।...

कांग्रेस के एक नेता ने चुटकी ली कि कोई बताए कि यह कहा किसके लिए गया है?

शिवसेना ने अर्थाया कि गडकरी जी ने अधिकांश जनता की भावना व्यक्त कर दी है।

यानी कि 'समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो अनाड़ी हैं!'

इतनी बढ़िया धांय धांय में सिद्धरमैया एक महिला के अपमान के चक्कर में कुटते रहे। महिला सामने माइक लिए शायद देर तक बोलती रही। फिर माइक खींचने के चक्कर में महिला की साड़ी का पल्लू खिंच गया। फिर क्या था, एक चैनल ने तुरत लाइन लगाई: 'कांग्रेस इंसल्ट्स इंडिया'! 'गलती' पूर्व सीएम की, लेकिन कुटाई सीधी कांग्रेस की। जबकि अन्य एक चैनल ने दिखाया कि महिला के हाथ से माइक खींचने के चक्कर में 'अनजाने पल्लू खिंच गया'।

कि इसी बीच राहुल ने फिर एक 'गेम चेंजर' मारा। वे एक रैली में बोले कि अगर चुनाव में जीते तो सभी गरीबों को 'न्यूनतम आय की गारंटी' देंगे। चैनल बताने लगे कि हर गरीब को बारह सौ से अठारह सौ रुपए तक मासिक आय दी जाएगी।

एक चैनल ने इसे 'राहुल का सिक्सर' कहा।'

एक भाजपा प्रवक्ता कहने लगे : मैं नहीं समझता कि ये कोई गेम चेंजर हैं! राहुल झूठ बोलने के आदी हैं उनकी साख नही हैं। कांग्रेसी तो खुद भ्रष्ट हैं।...

अभिषेक मनु सिंघवी बोले : यह योजना सभी के लिए है। अगर राहुल घोषणा करते हैं तो क्या परेशानी है, आप उसके आगे देखें।...

एक अर्थशास्त्री ने पूछा : लेकिन कौन गरीब है, इसका पता कैसे लगाएंगे?

एक अन्य भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल कोई नई बात नहीं कह रहे। पीएम ने गरीबों पर फोकस किया है। अभी डिटेल्स तो दें एमपी में किसानों को क्या दिया इन्होंने?

एक प्रो-राहुल पत्रकार कहने लगे : कांग्रेस आजकल एंजेडा सेट कर रही है। भाजपा सिर्फ प्रतिक्रिया करती है।

मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित स्थल को छोड़ बाकी सड़सठ एकड़ अविवादित जमीन को अधिग्रहीत करने की अनुमति दी जाए, ताकि उसे रामजन्म भूमि न्यास को दिया जा सके।...

यह सप्ताह का आखिरी गेम चेंजर रहा। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह पॉजिटिव कदम है।

योगी जी ने इसका स्वागत किया। अयोध्या के बाबा लोगों ने इसका स्वागत किया। एक धर्म नेता ने तो एक चैनल की बातचीत में यहां तक कह दिया कि बसंत पंचमी के दिन रामलला का भव्यमंदिर बनाने की शुरुआत की जा सकती है!